राज्य-वार कितनी टाडा अदालतें गठित की गईं ;

(ग) 30 जून, 1997 की स्थिति के अनुसार इन मामलों में राज्य-वार कितने अभियुक्त हैं ;

(घ) 30 जून, 1997 की स्थिति के अनुसार कितने व्यक्तियों को जमानत पर रिहा किया गया ;

(ङ) 30 जून, 1997 की स्थिति के अनुसार कितने व्यक्ति नजरबंद है ;

(च) पिछली बार टाडा मामलों की राज्य-वार समीक्षा कब की गई थी ; और

(छ) पिछली बार इन मामलों की केन्द्र सरकार द्वारा कब समीक्षा की गई थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (छ) यह सूचना केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है, हालांकि अन्य आपराधिक कानूनों की तरह टाडा, 1987 भी केन्द्रीय अधिनियम है लेकिन इसे लागू करने की जिम्मेवारी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की है। टाडा, 1987 के व्यपगत हो जाने के बाद राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की अभियोजन शाखाओं और पदनामित टाडा न्यायालयों द्वारा लम्बित मुकदमों को तेजी से निपटाया जाना है। एक प्रशासनिक उपाय के रूप में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से यह सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तर पर बार-बार अनुरोध किया गया है कि लम्बित मामलों की राज्य स्तर पर नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाए और लम्बित मामलों में विचारण तेज किया जाए, जिसके लिए यदि आवश्यक हो तो और पदनामित न्यायालय सृजित किए जायें। केन्द्रीय स्तर पर टाडा मामलों का नियमित प्रबोधन और पुनरीक्षा की जाती है। इस मामले की पुनरीक्षा करने के लिए अब केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री स्तरीय पैनल गठित किया गया है, जिसकी बैठक जल्दी होगी।

Overstaying of Foreign Nationals

2389. SHRI BHAGABAN MAJHI:

SHRI DILIP SINGH JUDEV:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of foreign nationals have overstayed in the country;

(b) if so, the approximate number of those nationals;

(c) whether they have gone underground; and

(d) if not, the efforts being made to traceout their whereabouts?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) to (d) As the powers under the Foreigners Act, 1946 to identify, detect and deport foreign nationals residing in the country beyond the validity of visa have been delegated to the State Government UT Administrations, such data is not Centrally maintained. The Government is, however, aware of the problem of foreign nationals residing in the country beyond the validity of their visas. Instructions have been issued to the State Governments/UT Administrations to detect and deport such foreign nationals.

Foodgrains for PDS smuggled to Bangladesh

2390. SHRI AKHILESH DAS:

SHRI SHIV CHARAN SINGH:

SHRI PARAG CHALIHA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether his attention has since been drawn towards a news-item entitled 'Foodgrains for PDS being